Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 2, April-2023, ISSN 2230-7540

हरियाणा का कृषि विकास : जिला महेन्द्रगढ का एक अध्ययन (1966-1978)

डॉ० नीरज कुमार*

सहायक प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बस्तली, करनाल।

Email: NK3958965@gmail.com

***शोध-सार-** यह शोध लेख हरियाणा राज्य के जिला महेन्द्रगह के कृषि क्षेत्र में हुए विकास का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है । हरियाणा प्रदेश की स्थापना के बाद हरियाणा के साथ-साथ जिला महेन्द्रगढ ने भी कृषि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी की है । इसके लिए हरियाणा सरकार ने जिले में हरियाणा लैण्ड एण्ड री-क्लेमेसन एण्ड डेवलमैण्ट कॉपरेटिव लिमिटिड, चण्डीगढ के माध्यम से जिले की भूमि को कृषि योग्य बनाया गया । हरित क्रान्ति आने के पश्चात् जिले में आधुनिक तकनीक से निर्मित औजार प्रयोग किये गए, सिंचाई-परियोजनाओं के द्वारा भी कृषि भूमि को लगातार सिचिंत किया गया । इसके अतिरिक्त जिले के जमींदारों व किसानों के द्वारा किए गए प्रयासों से भी कृषि उत्पादन लगातार वृद्धि हुई । जिसके परिणामस्वरूप जिले के कृषि उत्पादन में वर्ष 966 से 978 तक 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।*

***मुख्य-शब्द -** हरित क्रान्ति, सिंचाई, कृषि विज्ञान कन्द्र, पशुपालन, कृषि योजनाएं, सहकारी समितियाँ।*

----------X----------

भूमिका

महेन्द्रगह हरियाणा के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक छोटा सा जिला है। यह 27०48'उत्तरी अक्षांश से 28०28' उत्तरी अक्षांश तथा 75०26' से 76०52' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।[1] 2001 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 1859 वर्ग किम्मी० था । यह हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 4.20 प्रतिशत भाग रखता था तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जिले में 11वां स्थान था ।[2]

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जिले की 82.30 प्रतिशत गांवों में निवास करती थी । इसलिए अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि था।[3] कृषि के क्षेत्र में हरियाणा राज्य की स्थापना के पश्चात् जिले ने काफी प्रगति की । क्योंकि उत्तम सिंचाई व्यवस्था, मशीनों, खाद, कीटनाशक दवाईयों के प्रयोग से उपज में बढ़ोतरी हुई थी ।[4]

वर्ष 1950-51 में जिला महेन्द्रगढ की कुल कृषि योग्य भूमि 196 हजार हैक्टेयय थी जो 1978 में बढ़कर 246 हजार हैक्टेयरहो गई। इस अवधि के दौरान कृषि उत्पादन 73.33 टन से बढ़कर 278.30 टन हो गया था । जिले के खाद्यान्न उत्पादन में 966 से 1978 तक 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।[5]

मार्च 1978 में जिले में कुल 298 हजार हैक्टेयर भूमि थी। जिसमें 5 हजार हैक्टेयर भूमि वनों के अधीन थी । 60 हजार भूमि जौताई के लिए उपलब्ध नहीं थी । 8 हजार हैक्टेयर भूमि बंजर, टीलों या टीबों से युक्त थी । लेकिन स्थानीय लोगों की रुचि इन रेतीले टीलों को समतल करने की थी । इसलिए सरकार ने "हरियाणा लेण्ड एण्ड री-क्लेमेसन एण्ड डैवलपमैन्ट कॉपरेटिव लिमिटिड, चण्डीगढ स्थापित करके महेन्द्रगढहू जिले की उबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाने के लिए अभियान शुरू किया । जिसके परिणामस्वरूप सरकार व किसानों के प्रयासों से 1978 के अन्त तक 280 हैक्टेयर भूमि को समतल किया गया जिससे 540 परिवार लाभान्वित हुए थे ।[6]

फसलें

महेन्द्रगह जिले में उगाने वाली फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता था : खरीफ व रबी । जिन्हें स्थानीय भाषा के 'सावनी' व 'साढी"' कहा जाता था । कोई भी फसल

www.ignited.in

समयानुसार नहीं पकती थी इसलिए इन दोनों के फसलों के बीच में फसलें बोई जाती थी जिन्हें "जायद खरीफ' व "जायद रबी' कहा जाता था।[7] खरीफ फसलों में बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार तथा रबी फसलों में गेहूं जो, चना, कपास, तिलहन शामिल थी तथा जायद फसलों में सब्जियों, तरबूज, मूंग तम्बाकू, हरा चारा इत्यादि ।[8]

सिंचाई

सिंचाई कृषि की रीढ़ होती है। कृषि का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि किसी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं कितनी है। प्रारम्भ में जिला महेन्द्रगढह का अधिकतर हिस्सा वर्षा पर निर्भर था । वर्षा की उचित मात्रा न होने पर यहां पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी ।[9]

इसलिए सरकार ने 1974-75 में सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए चौधरी बंसीलाल ने जिले में "जवाहर लाल नेहरु सिंचाई परियोजना' शुरू की । इस नहर की कुल लम्बाई 1531 कि०मी० थी । जिसमें मुख्य चेनल की लम्बाई 782 कि०मी० थी। इस नेटवर्क में 68 पम्प हाउस लगे हुए थे । महेन्द्रगढ जिले में इसकी लम्बाई 616.279 कि०मी० थी । इस परियोजना में कुल 200 क्यूसिक पानी में से 600 क्यूसिक पानी सुनिश्चित किया गया। परन्तु इसमें से जिले में 300 क्यूमिक पानी की आपूर्ति की जाती थी।[10]

नहरी पानी के द्वारा जिले की सम्पूर्ण भूमि को सिंचित करने की क्षमता न होने पर लोगों ने सिंचाई के अन्य साधनों जैसे कुओं व नलकापों द्वारा सिंचाई करनी शुरू कर दी ।[11]

कुएं 1978 तक सिंचाई के प्रमुख साधन थे । कुओं से पानी निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति प्रयोग की जाती थी जिसको 'रहट' कहा जाता था । इस विधि द्वारा अधिक भूमि सिंचित नहीं की जाती थी । लेकिन बुजुर्गों के शब्दों में 'खाण जौगे दाणे होज्या ज्या करदें । इस विधि द्वारा 5 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती थी ।[12]

लेकिन समय के साथ हरित क्रान्ति आने से हरियाणा राज्य में विभिन्न वैज्ञानिक तरीक अपनाए गऐ । जिसमें जिला महेन्द्रगढ भी इस मामले में पीछा नहीं रहा । सबसे पहले लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से "नलकूप' लगाए गए ताकि आवश्यकता के समय सिंचाई के लिए सुगमता से पानी उपलब्ध हो सके । जिला महेन्द्रगढ में 966 में नलकूपों की संख्या 1221 थी जिनकी संख्या 1978 में बढ़कर 12540 हो गई थी ।[13]

सरकार द्वारा जिले में बाढ़ नियन्त्रण के लिए बांध भी बनवाए थे । जिसमें वर्षा ऋतु में पानी एकत्रित किया जाता था । जिसको बाद में सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता था । इन बांधों में सबसे महत्वपूर्ण बांध 'हमीदपूर बांध" था ।[14]

अतः महेन्द्रगढ जिले में मुख्य रूप से सिंचाई के साधन नहरें, कुएं, नलकूप व बाँध थे जिनसे भूमि का 44.3 प्रतिशत भाग सिंचित किया जाता था।[15]

कृषि औजार

सिंचाई के साथ कृषि औजारों ने भी जिले के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था । क्योंकि हरित क्रान्ति के पश्चात् पुराने कृषि औजारों की बजाए आधुनिक तनीक से निर्मित औजार प्रयोग किए जाने लगे थे जैसे फलसी क्लीवेटर, हेरा, ट्रैक्टर । जिले में 1966 में 73 ट्रैक्टर प्रयोग किये जाते थे जिनकी संख्या 978 में बढ़कर 528 हो गई थी।[16]

हरित क्रान्ति से पहले कृषि उपज के कम होने का प्रमुख कारण किसानों द्वारा साधारण किस्म के बीजों का प्रयोग करना था।[17] लेकिन हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप सरकार ने कम दामों पर उच्च उपज किस्म के बीज उपलब्ध करवाए । किसानों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जिससे कृषि उत्पादन में काफी प्रगति हुई । इस समय गेहूं के लिए पी०यू 18, पी०बी०डब्ल्यू, 343, चना के लिए पी०आर० 7, बाजरा के लिए कोल 20, हरियाणा 3, गन्ना के लिए शकर, उड़ान आदि बीजों का प्रयोग किया जाता था।[18]

इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1971-78 में "किसान आयोग" का गठन किया। जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कम से कम ब्याज पर ऋण देकर उनकी ऋण सम्बन्धी समस्याओं को दूर करना था तथा साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना था।[19]

कृषि विज्ञान केन्द्र

जिले में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किसानों को दी जाने वाली सलाह से भी कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ । क्योंकि कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा गांवों में जाकर कैम्प लगाए जाते थे। इस कैम्पों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता था तथा फसलों की बीमारी के उपचार के लिए नई दवाईयों की जानकारी भी दी जाती थी ।" साथ-साथ मधुमक्खी पालन, डेयरी उत्पादन

www.ignited.in

की सलाह भी दी जाती थी।[20] जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती थी तथा कृषि पर निर्भरता कम होती थी।[21]

महेन्द्र जिले में फसल के उत्पादन को बेचने के लिए सरकार की तरफ से मण्डियों की व्यवस्था की गई थी ताकि किसान बिना किसी बाधा के बची हुई फसल को इन मण्टडियों में बेच सके और अपने जीवन का निर्वाह कर सके । जिला महेन्द्रगढ की प्रमुख मण्डियां इस प्रकार थी जैसे नारनौल मण्डी, महेन्द्रगढ़ मण्डी, अटेली मण्डी, कनीना मण्डी। [22]

पशुपालन

हरियाणा के ग्राम्य जीवन के आर्थिक ढांचे में पशुपालन ने सदा ही महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है । क्योंकि पशुपालन का कृषि से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहा है । क्योंकि पशु किसान की अतिरिक्त पूंजी थे । 1971 की जनगणना के अनुसार जिले में पशुओं की संख्या 309730 थी तथा 1977 में इनकी संख्या बढ़कर 438900 हो गई थी।[23]

इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा किसानों की ऋण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकारी समितियों की स्थापना भी की थी । इन समितियों के माध्यम से कम ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जाता था । जिसके माध्यम से किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयां खरीद सकते थे । जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में लगातार बढोतरी हुई थी। [24]

निष्कर्ष

अत: उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि जिला महेन्द्रगढ ने हरियाणा प्रदेश की स्थापना के बाद लगातार कृषि क्षेत्र में विकास किया था । वर्ष 1966 से 1978 तक कृषि उत्पादन में लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यह वृद्धि हरियाणा सरकार के प्रयासों के साथ-साथ स्थानीय किसानों व जमींदारों के प्रयासों का भी परिणाम था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जिला महेन्द्रगढ गजेटियर, 988, पृ० 1
2. उपरोक्त
3. सांख्यिकीय हैण्डबुक, महेन्द्रगढ, 2004, पृ० 47
4. जिला महेन्द्रगढ् एक परिचय, 200, पृ० 17
5. सांख्यिकीय हैण्डबुक, महेन्द्रगह, 98, पृ० 68
6. जिला महेन्द्रगह गजेटियर, 988, पृ० 85
7. कृषि उपनिदेशालय रिपोर्ट, 984, नारनौल, पृ० 5
8. उपरोक्त
9. जिला महेन्द्रगढह गजेटियर, 988, पृ० 70-74
10. उपरोक्त
11. कृषि उपनिदेशालय रिपोर्ट, 98, नारनौल, पृ० 7-8
12. साक्षात्कार पर आधारित, अमरसिंह, किसान गांव खटोटीकलां, दिनांक 2.7.2022
13. सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा, 4984, पृ० 73
14. सिंचाई विभाग रिपोर्ट, 98, नारनौल, पृ० 10-11
15. उपरोक्त
16. सांख्यिकी सारांश, हरियाणा, 2001, पृ० 137
17. साक्षात्कार पर आधारित, अनीता, किसान, गांव खटोटीकलां, दिनांक 24.7.2022
18. कृषि उपनिदेशालय रिपोर्ट, 98, नारनौल, पृ० 4-6
19. कृषि हैण्डबुक, हरियाणा, 2004, पृ० 20-22
20. कृषि विज्ञान केन्द्र रिपोर्ट, महेन्द्रगह, पृ० 7-0
21. उपरोक्त
22. मार्कोट कमेटी रिपोर्ट, 98, नारनौल, पृ० 17-21
23. सांख्यिकी सारांश, हरियाणा, 200, पृ० 280-86
24. साक्षात्कार पर आधारित, कर्मवीर सिंह, कृषि सहकारी समिति कार्यरत अधिकारी, नारनौल, दिनांक 25.4.2022

Corresponding Author

डॉ० नीरज कुमार*

सहायक प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बस्तली, करनाल